प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

बदलाव की इच्छा रखने भर से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि काम करने से ही बदलाव आएगा।
- निक वुजिसिस

ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता

राजनीतिक चंदे से संबंधित एडीआर की ताजा रिपोर्ट इसी धारणा को पुष्ट करती है कि कॉरपोरेट फंडिंग का बड़ा हिस्सा हमेशा सत्तारूढ़ दल को मिलता है। इसके बावजूद कॉरपोरेट चंदे में भारी वृद्धि और पारदर्शिता की कमी चिंतनीय तो है ही।

सत्ता और पूंजी

एसोसिएशन

फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट न केवल राजनीतिक चंदे में कॉरपोरेट घरानों के बोलबाले के बारे में बताती है, बल्कि यह इस धारणा को भी और पुख्ता करती है कि उद्योग घरानों के चंदे का बड़ा हिस्सा हमेशा ही सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 2016 से 2018 के बीच भाजपा को कॉरपोरेट घरानों से 915 करोड़ रुपये चंदा मिला, जो कांग्रेस को मिले 55.36 करोड़ से सोलह गुना ज्यादा है! आजादी के बाद कांग्रेस को भी उद्योगपतियों के चंदे का बड़ा हिस्सा मिलता था। हालांकि 1960 के दशक में टाटा-बिड़ला जैसे उद्योग घराने कांग्रेस के अलावा मुक्त व्यापार की पैरोकार स्वतंत्र पार्टी को भी चंदा देते थे। वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगा देने के बावजूद गुपचुप तरीके से कॉरपोरेट फंडिंग जारी रही। इसमें वृद्धि हालांकि नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद आई, फिर भी वह आज की तुलना में कम ही थी। वर्ष 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने कंपनीज ऐक्ट में संशोधन कर कॉरपोरेट फंडिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर साढ़े सात फीसदी करने के साथ कॉरपोरेट ट्रस्ट को कानूनी वैधता प्रदान की, तो 2017 में एनडीए सरकार ने कंपनीज ऐक्ट में फिर संशोधन करने के अलावा एफसीआरए में संशोधन कर देश में रजिस्टर्ड विदेशी कंपनियों को भी कॉरपोरेट चंदे के लिए अधिकृत कर दिया और इलेक्टोरल बांड्स की शुरुआत की। इन्हीं वजहों से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में कॉरपोरेट चंदे का हिस्सा बढ़ता गया है- 2004-05 में कुल कॉरपोरेट चंदा 26 करोड़ था, जो 2017-18 में बढ़कर 422 करोड़ रुपये हो गया। ऐसे ही 2016 से 2018 के बीच राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे का 93 प्रतिशत कॉरपोरेट घरानों से मिला है। सिर्फ यही नहीं कि राजनीतिक चंदे में कॉरपोरेट क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी से राजनीतिक फैसलों में कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इलेक्टोरल बांड्स तो पारदर्शिता के सिद्धांत के भी खिलाफ हैं। लिहाजा एडीआर की इस रिपोर्ट को चिंता के साथ देखने के साथ-साथ यह प्रासंगिक सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में पारदर्शिता की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां चंदे के मामले में पारदर्शिता की जरूरत क्यों नहीं महसूस करतीं।

बढ़ती आबादी बढ़ाएगी प्रवासन

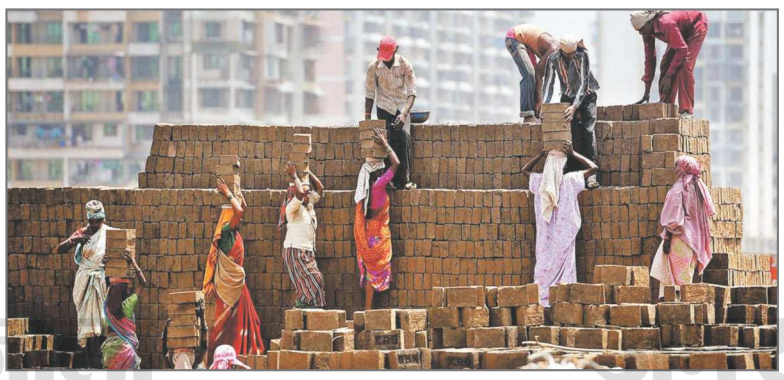

जब तक राज्यों के नीति निर्माता बुनियादी सुविधाओं और संरचनाओं के लिए योजना नहीं बनाते हैं और प्रवासी मजदूरों पर निर्भर रहते हैं, तब तक मेजबान समुदायों में नाराजगी बनी रह सकती है।

पत्रलेखा चटर्जी, वरिष्ठ पत्रकार

सबसे पहले एक अच्छी खबर! हम इस बात पर खुश हो सकते हैं कि भारत अगले दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट के लिए तैयार है। और यह कि आबादी बहुल हिंदी प्रदेश में बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह एक आशाजनक संकेत है। वर्तमान रुझानों के अनुसार, अगले दो दशकों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर आधी फीसदी हो सकती है, सिर्फ बिहार में ही जनसंख्या वृद्धि दर एक फीसदी रहने की संभावना है।

लेकिन जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण-2019 हमें बता रहा है, झारखंड के साथ ये राज्य अब भी 2021-41 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि में दो-तिहाई के हिस्सेदार होंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार ही जनसंख्या वृद्धि में 40 फीसदी से ज्यादा के लिए जिम्मेदार होंगे। जनसांख्यिकीय लाभांश, जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं, वास्तव में कामकाजी उम्र श्रेणी में जनसंख्या का उभार है। हिंदी प्रदेश लगातार जितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उसकी तुलना में ज्यादा रोजगार तलाशने वालों को पैदा करते रहेंगे। यह जमीनी हकीकत है। लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने और आकर्षित करने वाले कारक पहले से ही उत्तरी भारत के लोगों के भारी विस्थापन का कारण रहे हैं, जिनके चलते उत्तर भारत के लोग ज्यादा विकसित दक्षिण भारतीय राज्यों का रुख करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण इसी बात की पुष्टि करता है कि इस प्रवृत्ति के आगे भी जारी रहने की संभावना है।

दक्षिण भारतीय राज्यों ने लगातार रोजगार सृजन के मार्ग का नेतृत्व किया है, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित रोजगारों में, इन्हीं विशेषताओं के कारण इस क्षेत्र में कंपनियों की संख्या, योग्य प्रतिभाओं के पुल की मौजूदगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान और तीन प्रमुख शहरी केंद्रों की सामीप्य निकटता है। लेकिन भारत के गरीब राज्यों के अनौपचारिक श्रमिकों के लिए दक्षिणी राज्यों के आकर्षण का केंद्र बने रहने की भी संभावना है।

आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि 22 बड़े राज्यों में से 11 में, जिनमें दक्षिणी राज्य भी शामिल हैं, कामकाजी उम्र की आबादी के आकार में 2031-41 के बीच गिरावट शुरू हो जाएगी। जबकि कामकाजी उम्र वाले और नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की संख्या जनसांख्यिकीय संक्रमण में पीछे रहने वाले राज्यों में 2041 से लगातार बढ़ती जाएगी, इनमें प्रमुख राज्य हैं-बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसे ही शिक्षाविद चिन्मय तुम्बे ने अपनी सुविचारित पुस्तक *इंडिया मूविंगः ए हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन* में 'द ग्रेट इंडियन माइग्रेशन वेव' कहा है। तुम्बे हमें बताते हैं कि यह प्रवासन उत्तर और दक्षिण में भारी वेतन अंतर के कारण दक्षिणी राज्यों की तरफ होगा।

ऐसा पहले से ही हो रहा है। तुम्बे लिखते हैं, 'भोजपुरी भाषी क्षेत्र लगातार प्रवासियों को बाहर भेजता रहेगा, जैसा कि सदियों से हो रहा है, और कई अन्य क्षेत्रों में मौसम के कारण पहले अर्ध स्थायी और फिर स्थायी प्रवास के लिए संक्रमण होगा।' केरल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मलयाली प्रवासी जगजाहिर हैं। लेकिन आज केरल भी भारत के अन्य राज्यों के श्रमिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

केरल स्थित सेंटर फॉर माइग्रेशन ऐंड इनक्लूजिव डेवलपमेंट (सीएमआईडी) द्वारा 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट लेबर माइग्रेशन टु केरला में पाया गया कि 25 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 194 जिलों के श्रमिक 2016-17 में केरल में काम कर रहे थे। इनमें से 20-25 फीसदी जिले मात्र आठ राज्यों से थे। प्रवासी मजदूर मात्र दक्षिण के पड़ोसी राज्यों-तमिलनाडु और कर्नाटक से ही नहीं आए थे, बल्कि ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के भी थे। अध्ययन के मुताबिक, केरल में मजदूरी की दर अपेक्षाकृत ज्यादा है, 'स्रोत राज्यों' से केरल के लिए सीधे ट्रेन है, वहां से आसानी से घर पैसा भेजा जा सकता है, और मोबाइल फोन के प्रवेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए घर की दूरी घटा दी है। निर्माण, आतिथ्य,वृक्षारोपण, लोहा और इस्पात, लकड़ी के फर्नीचर, समुद्री मछली पकड़ने, खनन और उत्खनन, प्लाइवुड, वस्त्र और परिधान, समुद्री भोजन और जूते, आदि केरल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो प्रवासी श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूरों का सबसे प्रमुख स्रोत राज्य है। अध्ययन के मुताबिक, केरल जाने वाले प्रवासी मजदूर मुख्यतः रोहिलखंड और पूर्वांचल के अलावा सहारनपुर के होते हैं। मुख्य रूप से ये अकेले पुरुष होते हैं, जो आजीविका की तलाश में केरल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शिल्पकार लकड़ी पर अपने नक्काशी कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अब केरल में फर्नीचर उद्योग में काम कर रहे हैं। सहारनपुर के कारीगरों को एर्नाकुलम के अलावा कासरगोड और मलप्पुरम जिलों में देखा जा सकता है। और इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी।

सीएमआईडी की रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि 'प्रवासी मजदूरों को जितनी केरल की जरूरत है, उतनी ही केरल को विभिन्न विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रवासी मजदूरों की आवश्यकता है और राज्य को प्रवासी समावेशन विकास की आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिकों के समावेशन को अकेले सरकार पर छोड़ने के बजाय एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में लिया जाना चाहिए।'

यह अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा है। प्रवासन कोई बुरी चीज नहीं है। देश में बढ़ती गतिशीलता से विविधता ही बढ़ती है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रवासी श्रमिकों और उनकी जरूरतों को एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता बनानी होगी।

जब तक विभिन्न राज्यों के नीति निर्माता बुनियादी सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के लिए योजना नहीं बनाते हैं और प्रवासी मजदूरों पर निर्भर रहते हैं, तब तक मेजबान समुदायों में भारी नाराजगी बनी रह सकती है। हम पहले ही प्रवासी विरोधी भावनाओं और आक्रोश की बुरी राजनीति को देख चुके हैं। अगर इसका समाधान नहीं किया गया, तो इससे सबको नुकसान हो सकता है।

अंतर्ध्वनि

>> वी. एस नायपॉल

खंडहरों में होने से हमारा समय-बोध गड़बड़ा जाता है

हम वास्तव में केवल उस झूठ के लिए दंडित होते हैं, जिसे हम स्वयं बताते हैं। कुछ भावनाएं वर्षों की दूरी खत्म कर देती हैं और असंभव स्थानों को जोड़ देती हैं। जो सरकार अपने कानून तोड़ देती है, वह आपको भी आसानी से तोड़ सकती है। अगर किसी लेखक को सब पता हो, जो होने जा रहा है, तो उसकी पुस्तक उसके शुरू करने से पहले ही मर जाएगी। मैं जानता था कि मुझे कहां जाना है। मैंने सही दरवाजा खटखटाया। खंडहरों में होने से हमारा समय-बोध गड़बड़ा जाता है। मैं अपनी किताबों का निचोड़ हूं। मेरे बारे में जो कुछ भी मायने रखता है, सब मेरी किताबों में है। लेखकों को लोगों को असहमति के लिए उकसाना चाहिए। हमें हमेशा स्थिति की सच्चाई देखने की कोशिश करनी चाहिए, इससे हम चीजों को सार्वभौमिक बना सकते हैं। अगर लेखक बैठकर बस दमन के बारे में बात करते रहेंगे, तो वे ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। जिस सभ्यता ने दुनिया भर पर कब्जा किया हो, उसे मरती हुई सभ्यता नहीं कहा जा सकता। एक लेखक की जीवनी में- या यहां तक कि उसकी आत्मकथा में भी- हमेशा अपूर्णता रहेगी। बदलाव के लिए आपको अपने अतीत को, अपने इतिहास को नष्ट करना होगा। आपको कहना होगा कि आपकी पैतृक संस्कृति नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं लिख रहा होता हूं, तो यह आश्चर्य का विषय होता है कि मैं क्या खोज रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं, उसके साथ न्याय करने का यह मेरा तरीका है, जो कभी आसान काम नहीं रहा है। कुछ लेखक सिर्फ बचपन के अनुभव के बारे में लिखते हैं, क्योंकि यह पूर्ण हो चुका होता है। लेकिन कुछ अन्य तरह के लेखक के लिए जीवन आगे बढ़ता रहता है। विषयों की तलाश के लिए मैंने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया है। शुरुआत में मेरे पास एक विचार, एक स्वरूप होता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही मैं समझ पाता हूं कि मैंने क्या लिखा है।

-भारतीय मूल के नोबेलजयी लेखक

मंजिलें और भी हैं

>> इर्तिका अयूब

बंदिशों को तोड़कर कश्मीरी लड़कियों को सिखा रही रग्बी

मैंने यह खेल इसकी तेज गति, ताकत और खून के बहाव को तेज करने के लिए चुना है। जब रग्बी गेंद आपके हाथों में होती है और आप गोल की ओर दौड़ते हो, तो वह गजब की अनुभूति है। मैं कश्मीर की रहने वाली हूं। मेरा खेलना परिवार में किसी को अच्छा नहीं लगता था। जब मैं हायर सेकंडरी मैं थी, तो घर वालों से छिपकर स्कूल में फुटबॉल खेलती थी। बाद में मेरे खेल शिक्षक ने मुझसे रग्बी में हिस्सा लेने को कहा। मुझे रग्बी के बारे में कुछ पता नहीं था। पर उनके कहने पर मैंने खेलना शुरू किया। स्कूल स्तर पर और फिर जिला स्तर पर स्वर्ण पदक जीता। लेकिन जब राष्ट्रीय टीम के लिए चयन हुआ, तो घर वालों ने बाहर भेजने से मना कर दिया। हलांकि बाद में मेरे चाचा ने उन्हें समझाया तो किसी तरह वे सहमत हुए।

मेरे पिता भी मेरे खेल के खिलाफ थे, हालांकि वह जब-जब टीवी या पत्र-पत्रिकाओं में मेरी तस्वीरें देखते तो खुश हो जाते थे। एक बार खेल के दौरान मेरी नाक टूट गई। परिवार के लोगों ने मेरे खेल का विरोध जोरदार तरीके से किया। परिचित तो यहां तक कहने लगे कि, अब तो इस लड़की से कोई शादी भी नहीं करेगा। उनके ताने सुनकर मैं मानसिक तनाव में चली गई। तब पापा ने मुझे संभाल लिया। एक बार तो मेरे सीनियर ही मेरी इज्जत पर सवाल उठाने लगे। धमका कर मुझसे रिजाइन ले लिया गया। मैं छह महीने तक तनाव में रही, लेकिन तब तक मेरे पापा मेरे समर्थन में आ गए, वह मुझे प्रोत्साहित करते रहे। जल्द ही मैंने वापसी की, और अकेले ही रग्बी लड़कियों की कोचिंग करने लगी।

कश्मीर घाटी में खिलाड़ी लड़कियों के लिए पहली मुश्किल परिवार की सरहदें लांघना होती है।

मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि खेल में भी लैंगिक अनुपात को प्राथमिकता दी जाए। इससे सामूहिक स्तर पर खेल का ही नुकसान होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़के की तुलना में कोई लड़की ज्यादा बेहतर टीम की कप्तान साबित हो, तो उसे ही अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव हो सकता है, जब लैंगिक स्तर पर समान टीम हो यानी लड़के और लड़कियां एक साथ। ट्रेडिशनल टीम उसी पुराने खांचें में दर्शकों के लिए भी उबाऊ हो चुकी हैं। ट्रेंड बदले, नए फॉर्मूले में टीमों का गठन हो, तो हमारे नए-पुराने सभी खेल और भी ज्यादा रोमांचक हो सकते हैं। मेरे खेल के चलते ही मुझे जम्मू-कश्मीर की सबसे कम उम्र की रग्बी विकास अधिकारी (आरडीओ) बनाया गया है। मुझे भी उसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जैसे की अन्य कश्मीरी लड़कियों को करना पड़ता है। मेरे पास खेल के सभी संसाधन मौजूद नहीं हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में गवर्नर के सलाहकार ने रग्बी के कुछ उपकरण दिलाने की मंजूरी दी थी पर वे अभी तक मिले नहीं हैं। बावजूद इसके, अब तक स्कूल-कॉलेजों के सैकड़ों बच्चों को मैं प्रशिक्षित कर चुकी हूं। अभी लगभग पचास कश्मीरी लड़कियां रग्बी सीख रही हैं। मैं चाहती हूं कि ये लड़कियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रग्बी खेलें।

कश्मीर घाटी में खिलाड़ी लड़कियों के लिए पहली मुश्किल परिवार की सरहदें लांघना होती है। इसके बाद परिचित व रिश्तेदार शादी-ब्याह के ताने मारते हुए रुकावट बनते हैं। मैंने इनको झेला है, मानसिक तनाव में भी रही हूं, पर कभी हार नहीं मानी। अब मेरे खेल को मेरा परिवार सहयोग करता है। हर तरह के खेल के लिए कश्मीर में प्रतिभाएं मौजूद हैं। यहां की लड़कियां चाहती हैं कि विभिन्न खेलों का हिस्सा बनें, लेकिन सामाजिक रूढ़ियों, पारिवारिक बंधनों व रिश्तेदारों के तानों के चलते उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। इन लड़कियों को जम्मू-कश्मीर खेल परिषद से बड़ी उम्मीदें हैं।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

घाटे के बजट पर क्षुब्ध पाकिस्तान

इमरान खान की सरकार ने पिछले महीने 70 खरब से ज्यादा का बजट पेश किया, जिसमें 35 खरब का घाटा है और जिसे वहां की गरीब जनता भरेगी। विपक्ष के विरोध के बावजूद अवाम-विरोधी बजट को संसद से मिली मंजूरी पर जनता में गुस्सा है।

कुलदीप तलवार

पाकिस्तान की जनता का प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार से मोहभंग होता जा रहा है। सरकार कह रही है कि एक दो साल की मुश्किल सूरते हाल के बाद जनता खुशहाली का दौर देखेगी, एक करोड़ नौकरियां मिलेंगी और बेघरों को 50 लाख घर बनाकर दिए जाएंगे। पर इसके लिए कोई ठोस योजना नहीं लाई गई। जब तक वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा नहीं होती, तब तक बिगड़ती आर्थिक हालत में सुधार नहीं होगा। आतंकी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ (फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स) ने हाल ही में लश्कर, जैश और अन्य आतंकवादी समूहों का वित्तीय पोषण रोक पाने में विफल रहने पर पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है। साथ ही, पाकिस्तान को सितंबर, 2019 तक कार्य योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने का समय दिया है। अगर इस पर भी पाकिस्तान ठोस कदम नहीं उठाता, तो उस पर प्रतिबंध (काली सूची में डालने का) का डर बना रहेगा। काली सूची में डाले जाने पर पाक अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर का झटका लगेगा, विदेशी निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और बीमा कंपनियां कारोबार के लिए ज्यादा प्रीमियम लेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को ज्यादा जोखिम वाला बाजार माना जाएगा।

कर्ज के लिए पाकिस्तान जगह-जगह हाथ-पैर मार रहा है, पर उसे अब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका की ओर से चेतावनी दी गई है कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले छह अरब डॉलर के पैकेज का इस्तेमाल चीन के लिए न किया जाए। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को दी जाने वाली 13 करोड़ डॉलर की मदद रोक चुका है।

इधर एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान की उस घोषणा से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि उसे इस बैंक से 3.4 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर हो गया है। पाकिस्तान के लिए यह शर्मनाक है। एक तरफ कर्ज देने वाली विदेशी संस्थाओं व बैंकों से कर्ज मिलने में बाधाएं आ रही हैं, वहीं उस पर डिफॉल्टर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उस पर 12 महीनों में 700 अरब के फंड की व्यवस्था करने का दबाव है। जबकि न केवल उसका राजस्व घाटा आसमान छू रहा है, बल्कि भुगतान संतुलन भी पटरी से उतर गया है। उसके आयात और निर्यात का अंतर बढ़कर 18.2 अरब डॉलर हो गया है, जो 2015 में मात्र 2.7 अरब डॉलर था।

सरकार ने बजट से पहले एक आर्थिक सर्वे जारी किया, जो मायूस करने वाला है और इस पर सरकार का रवैया भी निराशाजनक है। सरकार ने नेशनल असेंबली में विगत 11 जून को 70 खरब से ज्यादा का सालाना माली बजट पेश किया था, जिसमें 35 खरब का घाटा है और जो पाक की गरीब जनता ही भरेगी। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद इस अवाम-विरोधी बजट को संसद ने मंजूर कर दिया है और इस पर जनता में रोष पनप रहा है। वहां के अखबार *जसारत* ने लिखा है कि बेहतर होगा कि इमरान खान पिछली सरकारों का रोना रोने के बजाय अपनी सरकार की एक साल की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएं। अगर पिछली सरकारों ने देश को लूटा है, तो उस रकम को वापस लाने के लिए इमरान खान ने अब तक कौन-सा तीर मारा है? इमरान खान को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार पाक के इतिहास की सबसे विफल सरकार है, जिसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। अगर हालात में सुधार न आया तो पाकिस्तान का नाम नाकाम देशों की सूची में शामिल होने की आशंका बढ़ जाएगी। देखना है कि अगले कुछ दिनों में पाक के हालात क्या शक्ल अख्तियार करते हैं।

खुली खिड़की

दूध का सर्वाधिक उत्पादन

दूध हमारे प्रतिदिन के खाद्य व भोज्य पदार्थों का अहम हिस्सा होता है। दूध का उपयोग पनीर, क्रीम, मक्खन, दही, आइसक्रीम सहित दूसरे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। दूध उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पर है।

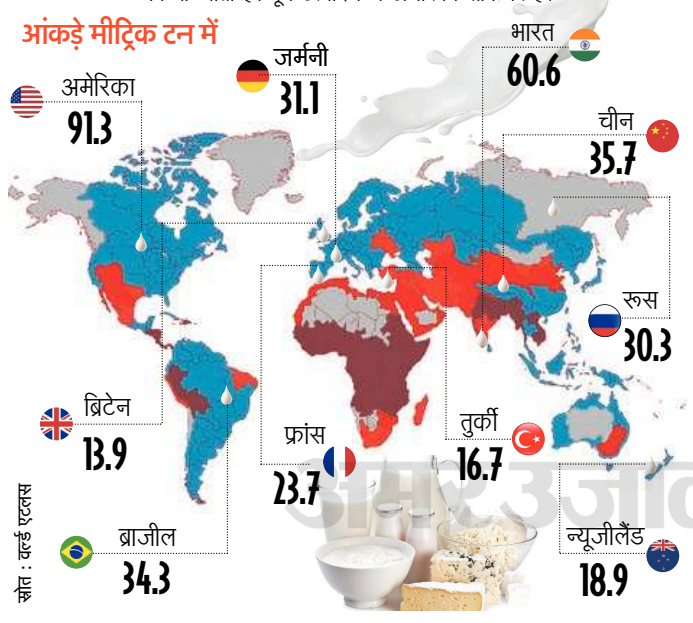

स्रोत : वर्ल्ड एटलस

संपत्ति की सार्थकता

सत्संग

कोलकाता में एक बार भीषण अकाल पड़ा। हजारों व्यक्ति तथा गाय-बैल अकाल की विकरालता के शिकार होकर दम तोड़ने लगे। स्थानीय सेठ मोहनदास अपार संपत्ति के मालिक थे। वह भगवान श्रीकृष्ण के परम उपासक भी थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को आदेश दिया कि, मकान के तहखाने में एक तिजोरी में सोने की अशर्फियां रखी हुई हैं। उन्हें तुरंत मेरे पास ले आओ। मुनीम तहखाने से अशर्फियां निकाल कर लाया और सेठ के सामने रख दीं। सेठजी बोले, मुनीम जी, इन अशर्फियों से खाद्यान्न तथा हरा चारा खरीदो। खाद्यान्न गरीबों में बांट दो और हरा चारा गाय-बैलों को खिला दो। सेठजी का युवा पुत्र वहीं बैठा था, जिसे आने वाले दिनों में पिता का कारोबार संभालना था। वह यह सुनकर चकित हो उठा। उसे अशर्फियां इस प्रकार खर्च कर देना मेहनत से कमाया गया अमूल्य धन लुटाने के समान प्रतीत हो रहा था। सेठजी पुत्र का चेहरा देखकर उसके भाव समझ गए। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, यदि ये अशर्फियां ऐसे संकट के समय तिजोरी में रखी रहेंगी, तो मैं भगवान को भला क्या मुंह दिखाऊंगा! तमाम धन मेरे इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण के ही तो हैं। मैं तो उनका मुनीम मात्र हूं। यदि इस धन से कुछ व्यक्तियों और गायों के प्राण बच गए, तो मेरा संपत्ति अर्जित करना सार्थक हो जाएगा। पिता की बात सुनकर बेटा संतुष्ट हो गया।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

मां, कमल और इंटरव्यू

यह कहानी एक गरीब विधवा के बेटे कमल की है, जिसे एक इंटरव्यू में परिवार की अहमियत का पता चला।

कमल पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। उसने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के इंटरव्यू के पहले तीन राउंड पार कर लिए थे। आखिरी राउंड में कंपनी के डायरेक्टर खुद इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या आपको कभी कोई स्कॉलरशिप मिली है? कमल ने कहा, नहीं। डायरेक्टर ने फिर पूछा, क्या आपके पिता घर के खर्च संभालते थे? कमल ने कहा, मैं एक साल का था, तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद से घर का खर्च मेरी मां चलाती हैं। डायरेक्टर ने पूछा, आपकी मां क्या करती हैं? कमल ने बताया, वह लोगों के घरों में कपड़े धोती हैं। डायरेक्टर ने कहा, क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूं? कमल ने अपने हाथ दिखा दिए। उसके हाथ मुलायम और बेदाग थे। डायरेक्टर ने पूछा, क्या आपने कभी कपड़े धोने में मां की मदद की? कमल ने जवाब दिया, मेरी मां चाहती थीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूं। डायरेक्टर ने कहा, आज घर जाकर अपनी मां के हाथ अच्छे से साफ करना, फिर कल मुझसे मिलना। घर लौटकर कमल ने मां से कहा, आज मैं आपके हाथ धोना चाहता हूं। मां को यह सुनकर अच्छा लगा। कमल ने देखा कि उसकी मां के हाथ कई जगह कटे हुए थे और उनमें गड्ढे भी पड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वह मां का दर्द महसूस कर पा रहा था। उस दिन सारे कपड़े कमल ने धोए। अगले दिन जब वह डायरेक्टर के पास पहुंचा, तो डायरेक्टर उसकी सूजी हुई आंखें देखकर पूरी कहानी समझ गए। उन्होंने कमल से पूछा, कल के अनुभव से आपने क्या सीखा? कमल ने कहा, मुझे पहली बार परिवार की अहमियत समझ में आई। डायरेक्टर बोले, मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था, जो रिश्तों और मूल्यों को पैसों से बढ़कर माने। हमारी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है।

पैसों के बजाय मूल्यों को महत्व देने वाले लोग जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं।